FINANCIAL EXPRESS, Delhi, 18.4.2025
Page No. 2, Size:(9.11)cms X (9.10)cms.

CGD firms may hike CNG prices by ₹2/kg after cut in allocation

ARUNIMA BHARADWAJ
New Delhi, April 17

THE RECENT REDUCTION of 18-20% in the allocation of administered price mechanism (APM) gas to city gas distribution (CGD) entities have clouded their profitability outlook. To compensate for this, CGD firms will need to increase the prices of compressed natural gas (CNG) by ₹1.5-2 per kg, analysts say.

The earnings of CGD companies have sharply declined in the last few quarters. "With further allocation cuts, the outlook is weaker," Kotak Institutional Equities said.

The government has cut the allocation of APM gas to CGD companies by up to 20% replacing it with equal or more volumes of new well gas (NWG), which is costlier.

"On our estimate, to pass on the entire cost, CGDs will need CNG price hikes of ₹1.5-2/kg. With reduced arbitrage versus petrol/diesel, the likely impact on demand and political sensitivity, price increases have been difficult," Kotak said.

CGD companies including Indraprastha Gas, Mahanagar Gas, and Adani Total Gas get domestic gas allocation for meeting the requirement of PNG and CNG sales volumes at the pricing fixed by the government, which is currently at $6.75/MMbtu. Analysts say that CNG price increases have been difficult politically and due to the likely impact on demand. With this cut, the APM allocation for the CNG segment is reduced to 37%.

"This is a similar allocation after two cuts in Q3FY25. As cuts were sudden and sharp, and price increases were difficult, there was partial relief in January and allocation for CNG was increased to ~51%. The latest cut nearly reverses the entire relief," the brokerage said.

The entire reduction in allocation has been made from the CGD sector while other consuming sectors such as fertiliser, power and LPG fractionation have been spared for now. Analysts expect that there could be a further decline in the allocation of APM gas to CGDs due to declining volumes.

COST RECOVERY

- Govt has cut APM gas allocation to city gas distribution companies by up to 20%
- These firms have instead been allocated new well gas, which is costlier
- APM gas allocation for CNG segment has been reduced and now stands at 37%
- APM gas allocation to sectors such as fertilizer, power and LPG has not been cut for now

FINANCIAL EXPRESS, Delhi, 18.4.2025
Page No. 2, Size:(3.02)cms X (9.05)cms.

Indian Oil-GPS JV to set up 10 biogas plants at ₹1,200 crore

RAGHAVENDRA KAMATH
Mumbai, April 17

IOC GPS RENEWABLES — a joint venture between Indian Oil Corporation (IOC) and GPS Renewables — is looking to set up 10 compressed biogas (CBG) plants this financial year at a cost of ₹1,200 crore.

The joint venture focuses on integrating advanced biogas technologies to convert organic waste into CBG, a renewable energy source. The CBG plants in Haryana, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, and Andhra Pradesh will have a capacity of 15 tonne per day, or 5,475 tonne per annum, of CBG and 50 tonne per day of products such as fertilisers and biomass pellets. The country has set a target of reaching 500 GW of non-fossil fuel capacity by 2030.

The company has secured leases for all the 10 land parcels and looking to begin construction of the plants this month, said Devendra Singh Sehgal, chief executive officer at IOC GPS Renewables. The JV was formed in June last year.

FINANCIAL EXPRESS
READ TO LEAD

PUNJAB KESARI, Delhi, 18.4.2025
Page No. 12, Size:(7.01)cms X (21.35)cms.

ईरान से तेल खरीदने पर चीनी रिफाइनरी पर लगा प्रतिबंधित

वाशिंगटन, (एपी) अमेरिका ने ईरान से एक अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य का तेल खरीदने पर चीन की एक रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस धन से ईरान की सरकार को और ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों को आर्थिक मदद मिलती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के अनुसार जिस रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया गया है उसे ईरान से कच्चे तेल की दर्जनों खेप प्राप्त हुईं, जिनकी कीमत एक अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार कुछ खेप ईरान के अर्द्धसैनिक बल "रिवोल्यूशनरी गार्ड" से जुड़ी एक कंपनी से थी। प्रतिबंध की इस सूची में कई कंपनी और पोतों के नाम शामिल हैं।

DAINIK TRIBUNE, Delhi, 18.4.2025
Page No. 9, Size:(7.91)cms X (9.62)cms.

किसानों का विरोध तेल पाइपलाइन काम शुरू करवाने पहुंची पुलिस व अधिकारी लौटे बैरंग

22 फरवरी को होगी किसानों व प्रशासन की मीटिंग : सतीश यादव

भिवानी, 17 अप्रैल (हप्र)

किसानों को बगैर मुआवजा दिए उनके खेतों से बिछाई जा रही तेल पाइप लाइन के विरोध में गांव रूपगढ़ में किसान पिछले 5 माह से लगातार धरने पर बैठे हैं। किसानों द्वारा 21 अप्रैल को भिवानी विधायक के अवास के घेराव की चेतावनी दी गई थी, लेकिन इससे पूर्व ही बृहस्पतिवार को गांव रूपगढ़ धरना स्थल पर भारी पुलिस फोर्स के साथ निजी कंपनियों के अधिकारी पहुंचे तथा किसानों को कथित तौर पर डरा-धमकाकर धरना खत्म करवाकर तेल पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू करने का प्रयास किया।

सूचना मिलते ही भारी तादात में किसानों ने धरनास्थल पर पहुंचकर पुलिस फोर्स व निजी कंपनियों के अधिकारियों की इस कार्रवाई का विरोध जताया। किसानों के रोष को देखते हुए पुलिस फोर्स व निजी कंपनी के अधिकारियों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इस दौरान गाड़ी में आए पाइपों को रोड़ के साइड में रखवाए जाने की अपील की, जिसकी इजाजत किसानों द्वारा दे दी गई। इस बारे में जानकारी देते हुए भाकियू (चढ़ूनी) के जिला अध्यक्ष राकेश आर्य ने बताया कि वीरवार को भी गांव रूपगढ़ में किसानों का धरना सतीश यादव व कमलजीत प्रधान के नेतृत्व में जारी रहा। राकेश आर्य ने कहा कि इस दौरान किसानों व प्रशासन के बीच 22 अप्रैल को मीटिंग पर भी सहमति बनी, जिसमें किसान खुलकर अपना पक्ष रखेंगे।

भिवानी में बृहस्पतिवार को पुलिस व निजी कंपनियों के अधिकारियों से बातचीत करते गांव रूपगढ़ के किसान। -हप्र

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निजी कंपनियों के साथ सांठ-गांठ कर खेतों में तेल पाइप लाइन बिछाई जा रही है, जिसकी एवज में किसानों को मुआवजा तक नहीं दिया जा रहा, जो सरासर किसानों को बर्बाद व निजीकरण को बढ़ावा देने की सोच को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि पहले किसानों को हाईटेंशन तार बिछाने के नाम पर प्रताड़ित किया गया तथा अब सरकार बिना मुआवजा उनके खेतों से पाइप लाइन बिछाकर उनकी जमीन को बंजर बनाना चाहती है, जिसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।

DAINIK JAGRAN, Meerut, 18.4.2025
Page No. 3, Size:(8.57)cms X (7.24)cms.

गैस एजेंसी दिलाने का झांसा देकर ठगे 12 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, मेरठ: मुंडाली के गांव मुरलीपुर फूल निवासी रीता ने कोर्ट के माध्यम से चार लोगों पर गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर 12 लाख रुपये ठगने का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

रीता ने थाने में दी तहरीर में बताया कि वर्ष 2023 में उन्होंने 80 लाख रुपये में अपनी जमीन बेची थी। कुछ महीने बाद पानीपत की सैनी कालोनी निवासी उनके रिश्तेदार सचिन राणा व उसकी पत्नी प्रियंका, राजेश और मोंटी उनके घर आए। इन लोगों ने उच्चाधिकारियों से पहचान होने की बात करते हुए गैस एजेंसी दिलाने की बात कही। आरोपितों ने उससे 20 लाख रुपये मांगे, जिस पर उसने 12 लाख रुपये नकद दे दिए। कई महिनों तक भी आरोपित गैस एजेंसी नहीं दिला सके।

गत एक फरवरी को आरोपित दोबारा से उनके घर आए और पांच लाख रुपये की मांग की। पीड़िता ने रुपये देने से इन्कार किया तो मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

RAJASTHAN PATRIKA, Delhi, 18.4.2025
Page No. 9, Size:(2.62)cms X (7.54)cms.

परेशानी

गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी

नई दिल्ली @ पत्रिका. केंद्र सरकार ने शहरी गैस वितरकों यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड और अदाणी टोटल गैस लिमिटेड को मिलने वाली कम लागत वाली एपीएम गैस सप्लाई में 20 प्रतिशत की कटौती कर दी है। इस फैसले का असर कंपनियों के मुनाफे पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अब उन्हें गैस की आपूर्ति की पूर्ति महंगे स्रोतों से करनी होगी। ताजा कटौती के बाद एपीएम गैस अब शहरी गैस जरूरतों का केवल 34% ही पूरा कर पाएगी, जबकि पहले यह आंकड़ा 51% था। एपीएम गैस की वर्तमान कीमत 6.75 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, जबकि नए कुओं से निकाली जा रही गैस की कीमत करीब 8 डॉलर प्रति यूनिट है। इससे कंपनियां बढ़ी हुई लागत ग्राहकों पर डाल सकती है।